RNI No. GUJHIN/2011/39228
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 105
दि. 13.08.2025, बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nakanram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

संक्षिप्त समाचार

पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बिगड़े बोल, सिंधु नदी के पानी को रोकने पर भारत को दी कड़ी गीदड़भभकी, क्या कहा?

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को एक बार फिर गीदड़भभकी दी है। उन्होंने इस्लामाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अगर भारत सिंधु नदी का पानी रोकने की कोशिश करता है तो उसे पाकिस्तान की एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगी।

यह बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच जल विवाद चरम पर है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भी भारत को पानी के बांध न बनाने की गीदड़भभकी दी थी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत ने अपना दो सप्ताह का ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, न्यायमूर्ति (डॉ.) विद्युत रंजन सारंगी ने प्रशिक्षुओं से मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में विकसित होकर हर व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा का बीड़ा उठाने का आग्रह किया 1,957 आवेदकों में से देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विविध शैक्षणिक विषयों के 80 विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुना गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत की दो-सप्ताह की ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप (ओएसटीआई) नई दिल्ली में शुरू हो गई है।

आईएसएलआरटीसी ने सीओडीए और एसओडीए के लिए आरपीएल-सीआईएसएलआई प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया

भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) ने विशेष रूप से सीओडीए (बधिर वयस्कों के बच्चे) और एसओडीए (बधिर वयस्कों के भाई-बहन) के लिए 15 दिवसीय आरपीएल - आईएसएल व्याख्या में प्रमाणन (सीआईएसएलआई) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। सुश्री ऋचा शंकर, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उप महानिदेशक ने आईएसएलआरटीसी, नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में जागरूकता, सामान्य एवं प्रचार (एजीपी) योजनाओं के उप सचिव श्री जसबीर सिंह उपस्थित हुए।

लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित किया, जिससे भारत के समुद्री भविष्य के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ

एक ऐतिहासिक घटनाक्रम में, लोकसभा ने भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 पारित कर दिया, जिससे भारत के समुद्री भविष्य के लिए एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यह अधिनियम भारत के बंदरगाह प्रशासन का आधुनिकीकरण करेगा, व्यापार में दक्षता बढ़ाएगा और वैश्विक समुद्री क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा।

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सबानंद सोनोवाल ने कहा, "यह विधेयक औपनिवेशिक काल के नियमों को प्रतिस्थापित करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर, विश्वस्तरीय समुद्री क्षेत्र के विजन को प्रतिबिम्बित करता है।"

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड को संबोधित किया। इस अवसर पर, प्रधानमंत्री ने 64 देशों के 300 से अधिक प्रतिभागियों के साथ जुड़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए भारत में प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत में परंपरा का मिलन नवाचार से होता है, आध्यात्मिकता का विज्ञान से और जिज्ञासा का संबंध रचनात्मकता से होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सदियों से, भारतीय आसमान को निहारते रहे हैं और बड़े प्रश्न पूछते रहे हैं।" उन्होंने आर्यभट्ट का उदाहरण दिया, जिन्होंने 5वीं शताब्दी में शून्य का आविष्कार किया था और यह बताने वाले पहले व्यक्ति थे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। प्रधानमंत्री ने कहा, "सचमुच, उन्होंने शून्य से शुरूआत की और इतिहास रच दिया!"

श्री मोदी ने कहा कि भारत की लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशालाओं में से एक वेधशाला मौजूद है। प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह वेधशाला सितारों के साथ हाथ मिलाने के लिए बहुत निकट है।" उन्होंने पुणे में विशालकाय मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप का उल्लेख करते हुए इसे दुनिया के सबसे संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप में से एक बताया, जो पल्सर, क्वासर और आकाशगंगाओं के रहस्यों को डिकोड करने में सहायता करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गर्व से स्क्वायर किलोमीटर एरे और लिगो-इंडिया जैसी वैश्विक मेगा-विज्ञान परियोजनाओं में योगदान देता है। उन्होंने याद किया कि दो वर्ष पहले, चंद्रयान -3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन बनकर इतिहास रचा था। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आदित्य-एल1 सौर वेधशाला के साथ सूर्य पर अपनी दृष्टि भी स्थापित की है, जो सौर फ्लेयर्स, तूफान और सूर्य के मिजाज की निगरानी करता है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना ऐतिहासिक मिशन पूरा किया, इसे सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण और युवा अन्वेषकों के लिए प्रेरणा बताया।

भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की

(जीएनएस)।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अधिकृत प्रतिनिधि श्री बृजमोहन श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आज नई दिल्ली के निर्वाचन सदन में बातचीत की और उनके सुझाव प्राप्त किए

यह बैठक निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के अध्यक्षों के साथ की जा रही बातचीत के क्रम में हो रही है। इन संवादों से रचनात्मक विचार-विमर्श की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता होती है जिससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी अध्यक्ष अपने सुझावों और चिंताओं को सीधे आयोग के साथ साझा कर सकें। यह पहल सभी हितधारकों के साथ मौजूदा कानूनी ढांचे के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को और मजबूत करने के आयोग के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस उत्सव पोरबंदर में : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा

गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी मेहसाणा में तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं कलेक्टर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ध्वज फहराएंगे

गांधीनगर, 12 अगस्त : भारत के स्वतंत्रता पर्व 15 अगस्त 2025 का राज्य स्तरीय उत्सव पोरबंदर में मनाया जाने वाला है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में पोरबंदर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) की विज्ञप्ति में बताया गया कि गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री शंकरभाई चौधरी मेहसाणा में तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं कलेक्टर विभिन्न जिला मुख्यालयों पर ध्वज फहराएंगे।

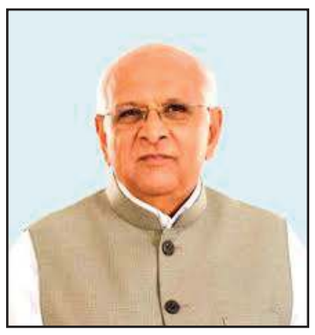

15 अगस्त स्वतंत्रता पर्व 2025

-: राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य एवं कलेक्टर इन जिलों में ध्वज फहराएंगे

:-

केबिनेट मंत्री

1. श्री कनुभाई देसाई. नवसारी, 2. श्री ऋषिकेशभाई पटेल. साबरकाँठा, 3. श्री राघवजीभाई पटेल , जामनगर, 4 श्री बलवंतसिंह राजपूत वलसाड,. 5 श्री कुँवरजीभाई बावळियागीर सोमनाथ. 6 श्री मुळुभाई बेरा द्वारका, 7 डॉ. कुबेरभाई डिंडोर पंचमहाल. 8 श्रीमती भानुबेन बाबरिया राजकोट

विधानसभा उपाध्याक्ष

9 श्री जेठाभाई आहिर (भरवाड) महीसागर

राज्य मंत्री

10 श्री हर्ष संघवी गांधीनगर, 11 श्री जगदीश विश्वकर्मा, मोरबी, 12 श्री मुकेशभाई पटेल, भरूच. 13. श्री भीखूसिंहजी परमार, खेडा, 14 श्री कुँवरजीभाई हळपति तापी

इसके अतिरिक्त; शेष जिलों में सम्बद्ध जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में ध्वजारोहण समारोह आयोजित होगा।

'स्वामित्व' (सर्वे विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) योजना की सफलता की गाथा नागरिकों को अपने भाग्य का स्वामी बनने के लिए सशक्त बनाती है: डॉ. जितेंद्र सिंह

(जीएनएस)।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि स्वामित्व (सर्वे विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज) योजना जैसी सफलता की गाथाओं ने नागरिकों को अपने भाग्य का स्वामी बना दिया है, जिससे राजस्व अधिकारियों और पटवारियों की दया पर दशकों की निर्भरता समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिक-केंद्रित शासन के एक वैश्विक मॉडल के रूप में उभरा है, जो नागरिकों द्वारा स्वयं भूमि का मानचित्रण करने में सक्षम बनाता है और अन्य देशों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद भवन में "भारतीय सर्वेक्षण विभाग" की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति 2022 को एक परिवर्तनकारी कदम बताया, जिसने भू-स्थानिक डेटा का लोकतंत्रीकरण किया है। इस पहल से सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक पहुंच और उपयोगिता संभव हुई है। उन्होंने बताया कि भारत के महापंजीयक के सहयोग से सीमाओं का सामंजस्य स्थापित करने का कार्य पूरा हो चुका है - जो हाल के वर्षों में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के परिवर्तन में एक मील का पत्थर है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वे ऑफ इंडिया की तकनीकी विशेषज्ञता कई प्रमुख योजनाओं का आधार है, जिनमें स्वामित्व योजना, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटीज, डिजिटल ट्विन मिशन और नक्शा योजना शामिल हैं। उन्होंने प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने, अन्य विज्ञान व सरकारी विभागों के साथ तालमेल बनाने तथा यह सुनिश्चित करने की योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की कि वे विभाग की विश्वस्तरीय सुविधाओं का पूर्ण उपयोग कर सकें।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) के विकास का हवाला दिया, जो मानचित्र निमार्ता से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए भू-स्थानिक सक्षमकर्ता बनने की दिशा में एक बदलाव है। उन्होंने मंत्रालयों के साथ विभाग की सक्रिय भागीदारी, साथ ही सतत संचालन संदर्भ केंद्रों (सीओआरएस) की स्थापना और राज्य, जिला एवं तालुका स्तर पर एक भूगणितीय संपत्ति रजिस्टर के निर्माण की सराहना की। तहसीलदारों को उपलब्ध कराए जाने वाले ये रजिस्टर नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बहुत आसान बना देंगे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली, 99.65% आधार सीडिंग का काम पूरा

(जीएनएस)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की बैंक खाता संख्या में बार-बार होने वाले बदलाव और उसके बाद उसे अपडेट न करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु, आधार भुगतान ब्रिज प्रणाली (एपीबीएस) लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 से अनिवार्य कर दिया गया है।

एपीबीएस से योजना के तहत मजदूरी वितरण की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने और लाभार्थियों के खाते में मजदूरी का त्वरित रूप से जमा होना सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। आधार प्रमाणीकरण भी धन को गलत हाथों में जाने से रोकता और भ्रष्टाचार को कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि मजदूरी केवल सत्यापित पहचान वाले वैध लाभार्थियों को ही प्राप्त हो। एपीबीएस के माध्यम से भुगतान में विफलता की स्थिति में, खाता-आधारित भुगतान के माध्यम से भुगतान करने का एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है जो नेशनल ऑटोमेटिड क्लियरिंग हाउस है। वर्तमान में, कुल 12.12 करोड़ सक्रिय श्रमिकों में से 99.65% आधार सीडिंग का काम पूरा हो चुका है।

एनआरईजीए सॉफ्ट में 100% आधार सीडिंग और एपीबीएस रूपांतरण प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य / केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर निगरानी की जा रही है। जब भी कोई मुद्दा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य हितधारक द्वारा चिह्नित किया जाता है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के अंतर्गत निगरानी और मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है।

रक्षा राज्य मंत्री ने नई दिल्ली में नाइजीरिया के रक्षा राज्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक की

(जीएनएस)।

रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने 12 अगस्त, 2025 को नई दिल्ली में नाइजीरिया के रक्षा राज्य मंत्री डॉ. बेलो मोहम्मद मटावाले के साथ

द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और विविध क्षेत्रों में सैन्य सहयोग को और आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद-रोधी प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास, जल सर्वेक्षण एवं समुद्री डकैती-रोधी सहित समुद्री सहयोग और उद्योग में सहयोग के अवसरों पर विचार-विमर्श किया।

रक्षा राज्य मंत्री ने हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और अपतटीय गश्ती पोत जैसे उच्च-गुणवत्ता वाले रक्षा उपकरण बनाने की भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने नाइजीरियाई पक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए नाइजीरिया के रक्षा अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की टीम का स्वागत करने की इच्छा व्यक्त की। नाइजीरियाई रक्षा राज्य मंत्री ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नाइजीरिया में रक्षा उद्योग का दौरा करने और इस क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया।

सम्पादकीय

वोट चोरी पर आर-पार की लड़ाई

लोकसभा चुनाव के 14 माह बाद एसआईआर और वोट बंदी के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट करने में सफल दिख रहा। भारत में राजनीति इस समय टॉप गीयर पर है। यह सही है कि भारत जैसे विशाल देश में चुनाव करवाना आसान नहीं है। यही नहीं भारत में इतने चुनाव होते हैं जो चुनाव आयोग की योग्यता के लिए चुनौती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत का चुनाव आयोग काफी हद तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने में सफल रहा है। वोट करना हर वोटर का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। यह भी जरूरी है कि उसका वोट उसे ही मिले जिसे उसने वोट दिया है। जब यह आशंका पैदा हो जाए कि उसका वोट दिया किसी को है और गया कहीं ओर तो बड़ा संदेह और निराशा पैदा हो जाती है।

किसी भी देश में लोकतंत्र की मजबूती-विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें सरकार को चुने जाने की प्रक्रिया कितनी स्वच्छ, स्वतंत्र और पारदर्शी है। इसके लिए चुनाव आयोजित कराने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न हो, मतदान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तथा चुनाव में हिस्सेदारी करने वाले सभी दलों के लिए भरोसेमंद हो और नतीजों को लेकर सभी पक्ष संतुष्ट हों। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र का डाटा पेश करते हुए आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में हेरापेरी हुई है।

दस्तावेज का ढेर मीडिया के समक्ष दिखाते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि यह सूची चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध मतदाता सूची के ढेर से निकली है। उनका दावा है कि महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा मतों की चोरी हुई है। संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि लोकसभा चुनावों, महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। तथ्यों के साथ राहुल ने साबित करने की कोशिश की।

मतदाता सूची में हेर-पेर, फर्जी मतदाता, गलत पते, एक पते पर कई मतदाता, एक मतदाता का नाम कई जगह की सूची में होने जैसे वुछ खास तरीकों पर आधारित वोट चोरी करने के इस माडल को कई निर्वाचन क्षेत्रों में अमल में लाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सके। हालांकि चुनाव गड़बिड़यां, ईवीएम में छेड़छाड़ की शिकायतें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन आमतौर पर वे किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकीं या फिर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें निराधार घोषित किया जाता रहा है। अब इस बार जिस गंभीर स्वरूप में इस मामले को उठाया गया है, उसके बाद देशभर में यह बहस खड़ी हो गई है कि अगर इन आरोपों का मजबूत आधार है तो इससे एक तरह से समूची चुनाव प्रक्रिया की वैधता कठघरे में खड़ी होती है। इस मसले पर चुनाव आयोग ने फिलहाल कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाए राहुल गांधी से शपथपत्र पर हस्ताक्षर कर शिकायत देने या फिर देश की जनता को गुमराह न करने को कहा है। मगर राहुल गांधी ने वोट चोरी का दावा करते हुए जिस तरह अपने आरोपों को सुबूतों पर आधारित बताया है।

उसके बाद चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह पूरी समूची प्रक्रिया पर भरोसे को बहाल रखने के लिए पूरी पारदर्शिता के साथ इस संबंध में उठे सवालों का जवाब सामने रखे। बहरहाल इस आरोप की गंभीरता को समझना आवश्यक है कि दो कमरों में क्रमश 80/46 लोग वैसे रह सकते हैं? इनमें तमाम मतदाताओं की तस्वीरें आकार में इतनी छोटी हैं कि पहचान करना मुश्किल है। इन आरोपों की पुष्टि आयोग को बगैर प्रत्यारोपों के करनी चाहिए। मतदाता सूचियों के प्रति आयोग जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। जो भी त्रुटियां सामने आती हैं उनके बारे में स्पष्टता से संतोषजनक जवाब देना चाहिए। सवाल आरोपों-प्रतिआरोपों का नहीं है। सवाल देश में संविधान की रक्षा का है जिसकी रक्षा तभी हो सकती है जब हर नागरिक को अपने वोट देने का अधिकार मिले और उसकी वोट उसे ही जाए जिसे वोट दिया गया है। हमारे लोकतंत्र की जड़ है स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव मगर इसमें भी हेरापेरी होती है तो हमारे संविधान व लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होती हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग प्रश्नों का संतोषजनक जवाब देगा और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाएगा।

व्यापार समझौते में विदेशी दबाव के बावजूद प्रधानमंत्री के मजबूत निर्णय के लिए किसान कृतज्ञ

देशभर के किसानों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मजबूत निर्णय का आभार व्यक्त करते हुए समर्थन किया

किसानों ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को अतुलनीय बताया

सभी किसान संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी एवं किसान हितैषी विचार का हृदय से स्वागत और पूर्ण समर्थन करते हैं

(जीएनएस)।

बड़ी संख्या में आज किसान संगठनों के प्रमुखों और देश के कोने-कोने से आए किसान भाइयों-बहनों ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के मजबूत कदम का स्वागत करते हुए धन्यवाद अर्पित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित सुब्रहमण्यम हॉल में किया गया था, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट सहित विभिन्न राज्यों के किसान संगठनों के नेता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सर्वप्रथम देशभर से आए किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने संबोधित करते हुए एक स्वर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की तथा किसान हितैषी ऐतिहासिक कदम के प्रति आभार व्यक्त किया।

भारतीय किसान संघ के श्री हरपाल सिंह डागर, श्री धर्मेंद्र मलिक, श्री धर्मेंद्र चौधरी, श्री विरेंद्र लोहान, श्री किरपा सिंह नत्थूवाला, श्री कुलदीप सिंह बाजिदपुर, बाबा राजेंद्र सिंह मलिक, श्री तरूणेश शर्मा, श्री के पी सिंह ठैनुआ, आचार्य रामगोपाल वालिया, श्री विनोद आनंद, श्री राजकुमार बालियान, श्री विनोद आनंद, श्री अशोक बालियान, श्री विपिचंद्र आर. पटेल, श्री रामपाल जाट, श्री कृष्णवीर चौधरी, श्री भूपेंद्र सिंह मान, श्री के. साई रेड्डी ने बारी-बारी से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के निर्णय के प्रति आभार व्यक्त किया।

भारतीय किसान चौधरी चरण सिंह संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र चौधरी ने कहा कि 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हित में अटल संकल्प वाला बयान दिया है। भारत किसी कीमत पर अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगा। ये घोषणा न केवल करोड़ो अन्नदाताओं को राहत देने वाली है, बल्कि कृषि एवं ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूती प्रदान करती है। हम इस दूरदर्शी एवं किसान हितैषी विचार का हृदय से स्वागत और पूर्ण समर्थन करते हैं। कृषि पशुपालन एवं मत्स्य हितों में ये प्रतिबद्धता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी।'

छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के किसान श्री विरेन्द्र लोहान ने कहा कि 'प्रधानमंत्री जी ने अमेरिकी कंपनियों को कृषि और डेयरी सेक्टर में प्रवेश नहीं देने का जो साहसिक निर्णय लिया है, वह हर खेत, हर गांव और हर गौशाला में गूंज रहा है। आपने अमेरिकी कंपनियों को प्रवेश न देकर ये सिद्ध कर दिया है कि, भारत का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि इस राष्ट्र की आत्मा है और इस आत्मा पर कभी कोई विदेशी कब्जा नहीं कर सकता। आपने हमें भरोसा दिलाया है कि, जब तक दिल्ली में वर्तमान नेतृत्व है, तब तक कोई भी ताकत भारत के किसानों को गुलाम नहीं बना सकती। मैं केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नकली खाद, बीज, कीटनाशक के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।'

श्री धर्मेंद्र मलिक ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 'हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और कृषि मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूं कि आपने जो स्टैंड लिया है, उस पर आप अडिग रहें और मुक्त व्यापार को लेकर हमारी नीतियों में कोई बदलाव ना लाए। हम सदैव आपके साथ हैं।'

श्री किरपा सिंह नत्थूवाला ने कहा कि 'हम बहुत चिंतित थे कि, अमेरिका समझौते को लेकर दबाव डाल रहा है, अगर समझौता हो जाता तो हम किसान बर्बाद हो जाते। लेकिन प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने किसानों के हित में कठोर निर्णय लिया है, इस निर्णय से पंजाब और देश के किसानों की छाती चौड़ी हो गई है। मैं देश के नागरिकों, किसानों और व्यापारियों को बताना चाहता हूं कि, अमेरिका चाहे जो बोलता रहे लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। कृषि मंत्री जी मैं आपको बधाई देता हूं और बताना चाहता हूं कि, देश का किसान आपके साथ खड़ा है।'

पंजाब से आए किसान श्री कुलदीप सिंह बाजिदपुर ने प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि किसान कल्याण के लिए सरकार अनेक कदम उठा रही हैं जिससे किसान भाइयों- बहनों की जिंदगी में बदलाव आया है। आगे हम आशा करते है कि सरकार और मजबूत कदम उठाएंगी ताकि हमें अमेरिका जैसे देशों की तरफ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री के निर्णय पर गर्व है।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि एक लघु भारत का दृश्य यहां दिखाई दे रहा है। मैं आपको प्रणाम करता हूं और यहां नीचे उपस्थित मेरे वो किसान भाई, जो दिन और रात मेहनत करके आज केवल भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खिलाने का समार्थ्य रखते हैं। अन्न हमारा जीवन है। अन्न ही ब्रह्म है। किसान अन्न देता है तो वो अन्नदाता भी है और वो जीवनदाता भी है। एक कृषि मंत्री के रूप में मुझे हमेशा ये लगता है कि किसानों की सेवा ही भगवान की पूजा है और इससे बड़ी पूजा कोई हो नहीं सकती।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर से दोहराया कि नकली खाद और उर्वरक बनाने वालों के खिलाफ सरकार जल्द ही नया कानून लाकर सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ही राजस्थान के झुंझुनूं से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा राशि का डिजिटल भुगतान भी किया गया।

केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री के राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प पर बल देते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता रद्द करना कर एक ऐतिहासिक निर्णय था। जिसके लिए हम प्रधानमंत्री के प्रति आभारी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सदैव राष्ट्र हित में मजबूत फैसले लिए हैं, जिनके प्रति देश आभारी है।

डीपीआईआईटी ने नवोन्मेषण गति केंद्रित आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स की सहायता करने और विस्तार देने के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

यह साझेदारी मोबिलिटी, क्लीन टेक और डीप टेक के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेगी

स्टार्टअप्स को हीरो मोटोकॉर्प की वैश्विक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, डीलर नेटवर्क और मेंटरशिप तक पहुंच प्राप्त होगी

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपने नवोन्मेषण में गति लाने वाले कार्यक्रम 'हीरो फॉर स्टार्टअप्स' के माध्यम से आरंभिक चरण के स्टार्टअप्स और उद्यमियों की सहायता करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, डीपीआईआईटी और हीरो मोटोकॉर्प संयुक्त रूप से मोबिलिटी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और गहन प्रौद्योगिकी के भविष्य से जुड़े क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेंगे। इस साझेदारी के तहत, चयनित स्टार्टअप्स को जर्मनी और भारत में हीरो मोटोकॉर्प की विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं,

कंपनी के डीलरों, आपूर्तिकताओं और साझेदारों के व्यापक नेटवर्क तथा मार्गदर्शन तक विशेष पहुंच प्रदान की जाएगी। चुने गए स्टार्टअप्स को सशुल्क प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) पर काम करने का अवसर भी मिलेगा, जिससे पायलट परियोजनाओं को सफल बनाने में सहायता मिलेगी और उनके नवोन्मेषणों के विकास और उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मूल्यवान बाजार अनुभव प्राप्त किया जा सकेगा।

इस अवसर पर डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने कहा कि हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी भारत की मोबिलिटी चुनौतियों का समाधान करने वाले उत्पाद-केंद्रित स्टार्टअप्स को सक्षम बनाने की डीपीआईआईटी की प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योग के अनुभव को जमीनी स्तर के नवोन्मेषणों से जोड़ने के द्वारा हमने, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों और टियर 2/3 बाजारों में, विचार से प्रभाव (आइडिया टू इम्पैक्ट) तक की यात्रा में तेजी लाने का लक्ष्य रखा है।

हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. पवन मुंजाल ने कहा कि कंपनी खुद को न केवल उद्योग जगत की एक अग्रणी कंपनी के रूप में, बल्कि एक राष्ट्र-निमार्ता के रूप में भी देखती है, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त किए गए विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि भारत का जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण शक्ति है। डीपीआईआईटी के साथ हमारी साझेदारी इस उद्यमशीलता की भावना को पोषित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दशार्ती है।"

समझौता ज्ञापन पर डीपीआईआईटी के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और हीरो मोटोकॉर्प के ग्लोबल इनोवेशन पोर्टफोलियो लीड श्री उत्कर्ष मिश्रा ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी से भारत के व्यापक लक्ष्यों मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत@2047 के अनुरूप नवोन्मेषण आधारित औद्योगिक विकास के लिए नए मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

तिरंगा यात्राः संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की नोडल संस्था ललित कला अकादमी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत जगाई देशभक्ति की लौ

(जीएनएस)।

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की नोडल संस्था ललित कला अकादमी (LKA), द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज फिरोजशाह रोड सर्कल पर भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। यह आयोजन सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का प्रबल प्रतीक बनकर उभरा, जिसने दिल्ली की सड़कों को तिरंगे के रंगों से जीवंत कर दिया।

सुबह 10 बजे शुरू हुई इस यात्रा में 1200 से अधिक स्कूली बच्चों, साहित्य जगत की प्रमुख व्यक्तियों और ललित कला अकादमी के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।यात्रा के दौरान तिरंगे के रंगों वाले गुब्बारे

आकाश में छोड़े गए, जो राष्ट्रीय एकता और गर्व का संदेश देते हुए आसमान में लहराए गए। प्रतिभागियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत गीत गाए और जोशपूर्ण नारों के साथ वातावरण को देशप्रेम की ऊर्जा से सराबोर कर दिया। तिरंगे के साथ कदमताल करते हुए बच्चों और अन्य प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और गौरव का संदेश जन-जन तक पहुंचाया।

ललित कला अकादमी, जो संस्कृति मंत्रालय के तहत कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है, ने इस आयोजन के माध्यम से कला, संस्कृति और देशभक्ति के अनूठे संगम को प्रदर्शित किया। यह यात्रा न केवल तिरंगे के प्रति सम्मान को दशार्या, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता को भी सशक्त करती है।

जिससे युवाओं में देशप्रेम की भावना को नया बल मिला। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ललित कला अकादमी का यह प्रयास तिरंगे के गौरव को हर घर तक पहुंचाने और समाज में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हुआ। इस आयोजन ने दिल्लीवासियों को एकजुट कर देशभक्ति की भावना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया।

'शिक्षार्थी' द्वारा बाल साहित्य के निजी पत्र संग्रह का अधिग्रहण

(जीएनएस)।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार के अप्रचलित अभिलेखों का संरक्षक है और लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों और शोधकताओं के उपयोग हेतु उन्हें न्यास के रूप में रखता है। एक प्रमुख अभिलेखीय संस्थान के रूप में, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार अभिलेखीय चेतना को दिशा देने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक अभिलेखों के विशाल संग्रह के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास जीवन के सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी पत्रों का समृद्ध और निरंतर बढ़ता संग्रह है, जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (एनएआई) ने प्रसिद्ध लेखक और कार्टूनिस्ट राम पदारथ 'शिक्षार्थी' (03 जून 1919 - 20 नवंबर 1981) द्वारा बनाए गए काटूनों, उपन्यासों और बाल साहित्य पर पुस्तकों का एक दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह प्राप्त किया है।

उनकी पुत्री सुश्री अल्पना निगम द्वारा दान किए गए इस संग्रह में उनके समय के सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित करने वाली विविध कृतियाँ शामिल हैं। जहाँ उनके कई राजनीतिक काटूनों ने उस युग की भावना को दशार्या, वहीं उनकी गैर-राजनीतिक कृतियों ने आम लोगों के दैनिक जीवन का हास्यपूर्ण और व्यंग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। "शिक्षार्थी" ने अपना स्वयं का प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया और भारत में स्वस्थ बाल साहित्य (बाल साहित्य) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुद्रित कृतियों के अलावा, इस संग्रह में हस्तलिखित सामग्री भी शामिल है जो भारतीय कला, साहित्य और समाज में शिक्षार्थी के योगदान को उजागर करती है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार देश की दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करने और उसे शोधकताओं, विद्वानों और आम जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4600 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को स्वीकृति दी

भारत सेमीकंडक्टर मिशनः कंपाउंड सेमीकंडक्टर और उन्नत पैकेजिंग क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, इस क्षेत्र में गति और बढ़ेगी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत चार और सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

भारत में सेमीकंडक्टर इकाइयों के अनुकूल परिवेश के निर्माण में तेजी आ रही है। इस क्षेत्र में छह स्वीकृत परियोजनाएं पहले से ही कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आज स्वीकृत ये चार प्रस्ताव सिकसेम (एसआईसीएसईएम), कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीडीआईएल), 3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक. और एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज (एएसआईपी) टेक्नोलॉजीज के हैं।

इन चार स्वीकृत प्रस्तावों के माध्यम से लगभग 4,600 करोड़ रुपये के कुल निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनियां स्थापित होंगी और इसी प्रकार से 2034 कुशल पेशेवरों के लिए रोजगार का सृजन होने की आशा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए अनुकूल परिवेश को गति मिलेगी और इसके परिणामस्वरूप अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत-सी नौकरियों का सृजन होगा। आज इन चार और प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ, भारत सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) के अंतर्गत 6 राज्यों में लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या 10 हो गई है।

दूरसंचार, ऑटोमोटिव, डेटा सेंटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए ये चार नई स्वीकृत सेमीकंडक्टर परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

सिकसेम (एसआईसीएसईएम) और 3डी ग्लास की स्थापना ओडिशा में की जाएगी। सीडीआईएल पंजाब में स्थित है और एएसआईपी की स्थापना आंध्र प्रदेश में की जाएगी।

सिकसेम प्राइवेट लिमिटेड ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में ब्रिटेन की क्लास-सिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ मिलकर सिलिकॉन कार्बाइड (एसआईसी) आधारित कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स का एकीकृत संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह देश की पहली व्यावसायिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई होगी। इस परियोजना में सिलिकॉन कार्बाइड उपकरणों का निर्माण प्रस्तावित है। इस कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब इकाई की वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर्स और पैकेजिंग क्षमता 9 करोड़ 60 लाख इकाइयों की होगी। प्रस्तावित उत्पादों का उपयोग मिसाइलों, रक्षा उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), रेलवे, फास्ट चार्जर्स, डेटा सेंटर रैक, उपभोक्ता उपकरणों और सौर ऊर्जा इन्वर्टर में किया जाएगा।

3डी ग्लास सॉल्यूशंस इंक. (3डीजीएस) ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित इन्फो वैली में वर्टिकल इंटीग्रेटेड एडवांस पैकेजिंग और एम्बेडेड ग्लास सबस्ट्रेट यूनिट स्थापित करेगी। भारत में यह इकाई दुनिया की सबसे उन्नत पैकेजिंग तकनीक लाएगी। इससे उन्नत पैकेजिंग सेमीकंडक्टर उद्योग में अगली पीढ़ी की सामर्थ्य हासिल होगी। इस सुविधा में पैसिव और सिलिकॉन ब्रिज वाले ग्लास इंटरपोजर और 3डी हेटेरोजेनस इंटीग्रेशन (3डीएचआई) मॉड्यूल सहित कई उन्नत तकनीकें उपलब्ध होंगी। योजना के अनुसार इस इकाई की क्षमता लगभग 69,600 ग्लास पैनल सबस्ट्रेट, 5 करोड़ असेंबल्ड इकाइयों और 13,200 3डीएचआई मॉड्यूल प्रति वर्ष होगी। प्रस्तावित उत्पादों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग रक्षा, उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आरएफ और ऑटोमोटिव, फोटोनिक्स और को-पैकेज्ड ऑप्टिक्स इत्यादि क्षेत्रों में होंगे।

एडवांस्ड सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज (एएसआईपी) दक्षिण कोरिया की एपीएसीटी कंपनी लिमिटेड के साथ तकनीकी साझेदारी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी जिसकी वार्षिक क्षमता 9 करोड़ 60 लाख इकाइयों की होगी। इसमें निर्मित उत्पादों का उपयोग मोबाइल फोन, सेट-टॉप बॉक्स, ऑटोमोबाइल संबंधी अनुप्रयोगों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में किया जाएगा।

कॉन्टिनेंटल डिवाइस (सीडीआईएल) पंजाब के मोहाली में अपनी भिन्न प्रकार की सेमीकंडक्टर निर्माण व्यवस्था का विस्तार करेगी। प्रस्तावित कंपनी में सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों में उच्च-शक्ति वाले भिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर उपकरणों का निर्माण किया जाएगा जैसे, एमओएसएफईटी, आईजीबीटी, शॉटकी बाईपास डायोड और ट्रांजिस्टर। पहले से चल रही इस कंपनी की वार्षिक क्षमता विस्तार के बाद 158.38 मिलियन इकाइयों की होगी। इन प्रस्तावित इकाइयों से निर्मित उपकरणों का उपयोग ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन और उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, विद्युत रूपांतरण अनुप्रयोग, औद्योगिक अनुप्रयोग और संचार संबंधी अवसंरचना शामिल हैं।

इन परियोजनाओं की स्वीकृति से देश में सेमीकंडक्टर के अनुकूल परिवेश के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इन परियोजनाओं में देश की पहली वाणिज्यिक कंपाउंड फैब्रिकेशन इकाई और अत्यधिक उन्नत ग्लास-आधारित सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई शामिल है।

ये परियोजनाएं देश में विकसित हो रही विश्व स्तरीय चिप डिजाइन क्षमताओं को और मजबूत करेंगी जिन्हें सरकार की ओर से 278 शैक्षणिक संस्थानों और 72 स्टार्ट-अप्स को प्रदान की जा रही डिजाइन अवसंरचना सहायता से बल मिल रहा है।

RNI No. GUJGUJ/2011/39228 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004, Ahmedabad,Gujarat-380 004. (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002 (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset,Bhatiya Ni Wadi, Opp Railway Station, Kalupur, Ahmedabad,-380002,Ahmedabad,Gujarat-380 002. and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH

जीएसआरटीसी टीम द्वारा अहमदाबाद मंडल के वॉर रूम का अवलोकन

अहमदाबाद मंडल, पश्चिम रेलवे स्थित वॉर रूम का दिनांक 12.08.2025 को, श्री एम. नागराज, क्अर, उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जीएसआरटीसी के मार्गदर्शन में, जीएसआरटीसी के वरिष्ठ मंडल यातायात अधिकारी श्री देव रांजिया ने टीम सहित अवलोकन किया।

इस दौरान टीम को वॉर रूम की कार्यप्रणाली, केंद्रीयकृत रेल मदद सेवा का 139 सेवाओं के साथ एकीकरण, तथा मंडल के समन्वित प्रतिक्रिया तंत्र की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि वॉर रूम 24ग्7 यात्री फीडबैक की निगरानी करता है, संबंधित विभागों से समयबद्ध समन्वय स्थापित करता है और शिकायतों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करता है। त्वरित प्रतिक्रिया, सटीक समन्वय और प्रभावी समाधान के इस मॉडल की जीएसआरटीसी टीम ने सराहना करते हुए इसे यात्री सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

इस दौरे से जीएसआरटीसी और भारतीय रेल के बीच यात्री सेवा सुधार एवं जन शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हुआ। श्री देव रांजिया ने अहमदाबाद मंडल की तकनीकी एकीकरण क्षमता एवं त्वरित प्रतिक्रिया हेतु सक्रिय कार्यप्रणाली की विशेष रूप से प्रशंसा की।

इस दौरान जीएसआरटीसी की टीम को वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, श्री अन्नू त्यागी द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

'हर घर तिरंगा' एवं स्वच्छता अभियान 2025 के अंतर्गत अहमदाबाद मंडल पर निकाली गई जागरूकता रैली

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल द्वारा "हर घर तिरंगा" अभियान और "स्वच्छता अभियान 2025" के अंतर्गत आज 12.08.2025 एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से प्रारंभ होकर यह रैली निर्माण भवन तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में रेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।

हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे और 'भारत माता की जय' एवं 'वंदे मातरम्' जैसे देशभक्ति नारों के साथ यह रैली देशप्रेम की भावना को जन-जन तक पहुँचाने का संदेश लेकर निकली। इस दौरान रेल कर्मियों और अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यालय तथा घरों में तिरंगा लगाने के लिए प्रेरित किया गया।

इसके साथ ही, 1 अगस्त से 14 अगस्त 2025 तक चल रहे "स्वच्छता अभियान 2025" के अंतर्गत मंडल में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंडल कार्यालय के कार्मिक विभाग द्वारा चित्रकला, प्रश्नोत्तरी एवं निबंध प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया, जिसमें रेल कर्मचारियों एवं केंद्रीय विद्यालय के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अहमदाबाद

मण्डल की सांस्कृतिक टीम द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया।

"हर घर तिरंगा" अभियान के अंतर्गत आयोजित ये कार्यक्रम कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने एवं स्वच्छता के प्रति जागरूककरने के उद्देश्य से आयोजित किए गए।

पश्चिम रेलवे पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है 'स्वच्छता अभियान'

पश्चिम रेलवे द्वारा श्रमदान और वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

फोटो कैप्शनः पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल में "स्वच्छता अभियान" के अंतर्गत की जा रही विभिन्न गतिविधियों की झलकियां।

भारतीय रेल द्वारा हमारे देश में मनाये जा रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह के एक भाग के रूप में और स्वच्छता एवं सार्वजनिक स्वच्छता के राष्ट्रीय हित के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि के लिए "स्वच्छता अभियान" मनाया जा रहा है। यह अभियान दो चरणों में अर्थात 1 से 15 अगस्त, 2025 तक और उसके बाद 16 अगस्त से 31 अक्टूबर, 2025 तक मनाया जा रहा है। यह अभियान रेलवे के सभी क्षेत्रों जैसे स्टेशनों, ट्रेनों, कॉलोनियों, कार्यालयों, डिपो और वर्कशॉप आदि में स्वच्छता के प्रति हमारे प्रयासों को दशार्ता है, साथ ही कर्मचारियों और यात्रियों में जागरूकता भी बढ़ाता है। पश्चिम रेलवे भी इस "स्वच्छता अभियान" में सक्रिय रूप से भाग ले रही है और इसके सभी मंडलों और इकाइयों में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम रेलवे का मुंबई सेंट्रल मंडल भी रेल कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ स्वच्छता अभियान के साथ-साथ अपनी दिनचर्या में बेहतर स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने

मना रहा है। कर्मचारियों और जन-स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी से कई स्थानों पर नुक्कड़ नाटक और स्वच्छता रैलियाँ आदि आयोजित की जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों और कार्यालयों में स्वच्छता और स्टेशन रखरखाव पर कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। इसी प्रकार, आम जनता से सीधे संपर्क रखने वाले कर्मचारियों के लिए भी विशेष कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से कर्मचारियों को स्वच्छता के सर्वोत्तम तरीके सीखने और ग्राहक सेवा में सुधार करने में मदद मिलती है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स टीम द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें रेलवे कर्मचारियों को स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए प्रेरित किया गया।

श्री विनीत ने आगे बताया कि मुंबई सेंट्रल मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों में श्रमदान और सघन सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान के दौरान रेलवे पटरियों के पास लगभग 2000 मीटर नालियों की सफाई की गई, जिससे बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित हुई। पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर केंद्रित जागरूकता अभियान विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इन अभियानों से स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिली है। मंडल के रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने प्रमुख स्टेशनों पर कूड़ा-कचरा विरोधी अभियान चलाकर यात्रियों से कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करने और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने का आग्रह किया जा रहा है। पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप मुंबई सेंट्रल स्थित कोच केयर सेंटर ने बायो-टॉयलेट के उपयोग पर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे कर्मचारियों की एक टीम मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों के साथ बातचीत कर रही है और उन्हें बायो-टॉयलेट के इस्तेमाल के फायदों और बेहतर स्वच्छता एवं कचरा प्रबंधन में इनके योगदान के बारे में जानकारी दे रही है। इसके अलावा लोगों को स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए स्वच्छता हस्ताक्षर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। खानपान कर्मचारियों के लिए जागरूकता अभियान और खाद्य प्रतिष्ठानों, पेंट्री कारों और बेस किचन में निरीक्षण भी चलाए जा रहे हैं। यात्रियों को प्लास्टिक कचरे को कम करने और कचरे का उचित निपटान केवल कूड़ेदानों में करने के लिए प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हरित पहल के तहत, विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस समारोह सप्ताह के दौरान स्वच्छता अभियान में पश्चिम रेलवे की सक्रिय भागीदारी स्वच्छता, स्थिरता और सार्वजनिक सहभागिता के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

हिम्मतनगरझखेड़ब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना पूर्ण होने के करीबः सीआरएस निरीक्षण जारी

"हिम्मतनगर-खेड़ब्रह्मा खंड के निरीक्षण के साथ, उत्तर गुजरात में रेल संपर्क के नए युग की शुरूआत

हिम्मतनगर,12 अगस्त 2025 - हिम्मतनगर और खेड़ब्रह्मा को जोड़ने वाली ऐतिहासिक मीटर गेज रेलवे लाइन, जो एक सदी से भी अधिक समय से साबरकांठा क्षेत्र की जीवनरेखा रही है, अब आधुनिक ब्रॉड गेज रूप में पुनः खुलने जा रही है। इस गेज परिवर्तन से तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल रेल सेवा मिल पाएगी।

हिम्मतनगरझखेड़ब्रह्मा गेज परिवर्तन परियोजना, जो गुजरात के साबरकांठा ज़िले में 55 किमी की दूरी को कवर करती है, इस परियोजना को 2 जून 2022 को ₹482 करोड़ की लागत से स्वीकृति मिली थी। इस परियोजना में पुरानी मीटर गेज लाइन को बेहतरीन ब्रॉड गेज ट्रैक से बदला जा रहा है, जिससे उच्च गति, बेहतर सुविधा और बढ़ी हुई मालवाहक क्षमता सुनिश्चित होगी। यह कार्य एढउ (इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन) अनुबंध के तहत किया जा रहा है, जो 28 मई 2023 को प्रदान किया गया था।

आज, पश्चिम रेलवे मंडल के रेल सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) ने वैधानिक निरीक्षण शुरू किया—जो कमीशनिंग से पहले एक आवश्यक कदम है। निरीक्षण हिम्मतनगर से शुरू होकर जादर तक 20 किमी की दूरी मोटर ट्रॉली द्वारा किया गया। टीम ने स्टेशन सुविधाओं, ट्रैक ज्योमेट्री, घुमाव, पुलों और रोड अंडर ब्रिज (फ्वइ२) की विस्तृत जांच की।

निरीक्षण टीम में श्री ई. श्रीनिवास, रेल सुरक्षा आयुक्त (उफ़र) (पश्चिम रेलवे मंडल), श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक अहमदाबाद, श्री प्रदीप गुप्ता,मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य ट्रैक इंजीनियर, मुख्य परिचालन प्रबंधक (जी) तथा निर्माण और ओपन लाइन विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

परियोजना का चरणबद्ध रूप से कमीशनिंग प्रस्तावित हैः

- हिम्मतनगर से इडर (31 किमी) - वर्तमान चरण में खोलने का लक्ष्य
- इडर से खेड़ब्रह्मा (23.83 किमी) - सितंबर 2025 तक खोलने का लक्ष्य

"यह परिवर्तन केवल गेज में सुधार नहीं है; यह साबरकांठा क्षेत्र के लिए कनेक्टिविटी, अवसर और विकास क्षमता में भी सुधार है।"

एक बार चालू हो जाने पर, आधुनिकीकृत लाइनः

- यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम करेगी
- तेज गति और समय पर सेवाएँ प्रदान करेगी
- कृषि, पत्थर उत्खनन और औद्योगिक वस्तुओं के लिए भारी और तेज माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करेगी

आज के निरीक्षण के साथ, हिम्मतनगर और ईडर-खेड़ब्रह्मा के बीच इस महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग के पुनः खुलने से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जो अब क्षितिज पर है और उत्तर गुजरात के लिए रेल संपर्क के एक नए युग की शुरूआत करेगा।

स्थानीय उत्साह और आर्थिक उम्मीदें

जादर के निवासियों ने आशा व्यक्त की है और अनुमान लगाया है कि यह परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देगी। वर्तमान में, जादर और हिम्मतनगर के बीच बसें एक से डेढ़ घंटे का समय लेती हैं, जिससे कनेक्टिविटी और बाजार तक पहुँच सीमित हो जाती है। ट्रेनें शुरू होने के बाद, किसानों और व्यापारियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है—खासकर गेहूँ, सब्ज़ियों और सूखे अनाज को अहमदाबाद के बाजारों तक पहुँचाने में, जहाँ उन्हें बेहतर दाम मिल सकते हैं।

एक स्थानीय व्यापारी ने कहा, "यह रेलवे समय की बचत करेगी, परिवहन लागत कम करेगी और व्यापार के नए अवसर खोलेगी। हमारे किसानों के लिए, इसका मतलब बेहतर मुनाफा और बड़े बाजारों तक पहुँच है।"

नेपाल की सियासत में हिंदुत्व की आहट! सीमा पार बढ़ रहे एकल विद्यालय, आरएसएस-वीएचएस पर क्यों टिकी नजर?

(जीएनएस)।

भारत के साथ खुली सीमा साझा करने वाला नेपाल (Nepal) अब एक नए राजनीतिक दौर से गुजर रहा है। पड़ोसी देश में अब हिंदुत्व की राजनीति तेजी से जड़ें जमा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से प्रेरित हिंदू स्वयंसेवक संघ (HSS) के नेतृत्व में एकल विद्यालयों और पशुपति शिक्षा मंदिरों के जरिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को मजबूती मिल रही है।

BBC की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल के बीरगंज जैसे इलाकों में एकल विद्यालय 1992 से चल रहे हैं। इन विद्यालयों में ज्यादातर दलित समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। यहां केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि हिंदुत्व के विचारों को

नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे मुद्दों पर संकल्प

इन स्कूलों में बच्चों को गोहत्या रोकने, धर्मांतरण के खिलाफ जागरूकता और नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने जैसे मुद्दों पर संकल्प दिलाया जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बीरगंज के सोनरनिया गांव में सुरेश पासवान के घर चलने वाले एकल विद्यालय के प्रमुख सोहनलाल प्रसाद साह खुलकर कहते हैं कि ये विद्यालय आरएसएस से जुड़े हैं। साह ने खुद गोरखपुर में आरएसएस की 21 दिनों की ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा लिया था।

एचएसएस (HSS) और आरएसएस (RSS) का संबंध

हिंदू स्वयंसेवक संघ (HSS) नेपाल सहित अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में सक्रिय है।

हालांकि, आरएसएस और एचएसएस अपनी वेबसाइटों पर आपसी संबंधों का जिक्र नहीं करते, लेकिन दोनों के बीच गहरा जुड़ाव स्पष्ट है। नेपाल में एचएसएस के 1048 एकल विद्यालय और 35 पशुपति शिक्षा मंदिर चल रहे हैं।

बीरगंज के पशुपति शिक्षा मंदिर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आरएसएस की शाखाओं जैसा माहौल, गणवेश और प्रार्थनाएं देखने को मिलती हैं। यहां तक कि स्कूलों में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर की तस्वीरें प्रमुखता से लगी हैं।

नेपाल में हिंदुत्व के नेतृत्व और प्रशिक्षण

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल में हिंदुत्व के अभियान में रवित कुमार और वेद प्रकाश जैसे लोग सक्रिय हैं, जो आरएसएस से प्रशिक्षित हैं। स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में भी होता है। एचएसएस के राष्ट्रीय संघचालक कल्याण कुमार तिम्सिना, जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन आरएसएस से संबंधों पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हैं।

नेपाल में हिंदुत्व की राजनीति का इतिहास पुराना है। आधुनिक नेपाल के निमार्ता पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को 'असली हिंदुस्थान' माना था। 19वीं सदी में मराठी ब्राह्मणों के प्रभाव और 1925 में आरएसएस के गठन के साथ नेपाल में हिंदुत्व के विचारों को बल मिला। 1960 के दशक में राजा महेंद्र के शासनकाल में आरएसएस के साथ निकटता बढ़ी, और 2008 में राजशाही खत्म होने के बाद भी हिंदुत्व की राजनीति ने जोर पकड़ा। 2014 में भारत में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में हिंदुत्व को और प्रोत्साहन मिला।

विरोध और चिंताएं

नेपाल में हिंदुत्व की बढ़ती सक्रियता को लेकर कई लोग चिंतित भी हैं। पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली और सांसद अमरेश सिंह जैसे लोग मानते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति नेपाल की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है।

मधेस में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, जैसे हनुमान जयंती और रामनवमी के दौरान हुई झड़पें, इस चिंता को और गहरा रही हैं। नेपाली कांग्रेस की सांसद जावेदा खातून का कहना है कि भारत की राजनीति का असर नेपाल में धार्मिक सौहार्द को प्रभावित कर रहा है।

नेपाल में हिंदुत्व की राजनीति का उभार, एचएसएस और आरएसएस की सक्रियता के साथ, एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को दशार्ता है।

कृषि और विपणन पर राष्ट्रीय नीति रुपरेखा (एनपीएफएएम)

(जीएनएस)।

विभिन्न राज्यों ने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) की स्थापना की है, क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है।

किसानों को बिचौलियों के हस्तक्षेप के बिना उचित मूल्य पर अपनी उपज बेचने में सुविधा प्रदान करने के लिए, सरकार ने 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म की शुरूआत की थी। ई-नाम प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण किसानों की बाजार पहुँच बढ़ाकर, बेहतर मूल्य निर्धारण, कम लेन-देन लागत, व्यापक बाजारों तक पहुँच, स्थानीय बाजार पर निर्भरता कम करके और बेहतर आय के अवसरों के माध्यम से महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाया है। यह प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करके और नकद लेनदेन की आवश्यकता को कम करके अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाया है और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है।

30 जून, 2025 तक, 23 राज्यों और 4 केन्द्र शासित प्रदेशों की 1,522 मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया जा चुका है। जून 2024 से जून 2025 तक, इस प्लेटफॉर्म पर व्यापार की मात्रा में 21 प्रतिशत और व्यापार मूल्य में 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार हर साल राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। 2014-15 से 2025-26 (30.06.2025 तक) के दौरान सरकार ने किसानों से 1,69,980.90 करोड़ रुपये मूल्य के 315.19 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद (तिलहन, दलहन और खोपरा) खरीदे हैं। किसानों के लिए मूल्य समर्थन प्रणाली (पीएसएस) और मूल्य न्यूनता भुगतान प्रणाली (पीडीपीएस) के योजना घटकों के माध्यम से विशेष रूप से दालों, तिलहन और खोपरा के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

शि योमी ज़िले में 8146.21 करोड़ रुपये परिव्यय से 700 मेगावॉट तातो-द्वितीय जल विद्युत परियोजना निर्माण के निवेश प्रस्ताव को मिली मंजूरी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में तातो-द्वितीय जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए 8146.21 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी। परियोजना पूरी होने की अनुमानित अवधि 72 महीने है।

700 मेगावॉट (4 ७ 175 मेगावॉट) की स्थापन क्षमता वाली यह परियोजना 2738.06 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेगी। परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने और राष्ट्रीय ग्रिड (भारत के विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों और उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली उच्च वोल्टेज विद्युत शक्ति संचरण प्रणाली) के संतुलन में भी सहायक होगी।

परियोजना नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ) और अरुणाचल

प्रदेश सरकार के बीच संयुक्त उद्यम वाली कंपनी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। केंद्र सरकार राज्य की हिस्सेदारी के मद में 436.13 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा, आवश्यक आधारभूत ढांचे - सड़क, पुल और संबंधित पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के तौर पर 458.79 करोड़ रुपये देगी।

इसमें राज्य को 12 प्रतिशत निशुल्क बिजली और एक प्रतिशत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) प्राप्त होने के अलावा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार और सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप यह परियोजना स्थानीय आपूर्तिकताओं/उद्यमों/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सहित कई प्रकार के लाभ प्रदान करेगी।

इस परियोजना के लिए लगभग 32.88 किलोमीटर सड़क और पुलों सहित बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार होगा, जिसका स्थानीय उपयोग हो सकेगा। ज़िले में 20 करोड़ रुपये की समर्पित परियोजना निधि से अस्पताल, स्कूल, बाजार, खेल के मैदान आदि बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी लाभ होगा। स्थानीय आबादी कई प्रकार के मुआवजे, रोजगार के अवसर और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों से भी लाभान्वित होगी।

डीपीआईआईटी ने जेप्टो नोवा इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए जेप्टो के साथ किया समझौता

हार्डवेयर, आईओटी, पैकेजिंग और दीर्घकालिक विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साझेदारी

(जीएनएस)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने अपने 'जेप्टो नोवा' इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए जेप्टो प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस सहयोग का उद्देश्य छह महीने के एकाग्र कार्यक्रम के माध्यम से स्टार्टअप्स की खोज और उनका मार्गदर्शन करना है। यह कार्यक्रम हार्डवेयर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, पैकेजिंग और दीर्घकालिक विनिर्माण के क्षेत्रों में तकनीक विकसित करने वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करेगा। वे जेप्टो के वितरण और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करके प्रोटोटाइप से बाजार तक के लिए तैयार समाधानों का विकास कर सकेंगे।

यह साझेदारी विशेषज्ञों के नेतृत्व में होने वाली कार्यशालाओं और स्टार्टअप इंडिया सहयोग के माध्यम से महिलाओं की मुख्य भूमिका वाले और टियर दो/तीन के स्टार्टअप्स पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण के संबंध में सहायता प्रदान करेगी।

इसके अतिरिक्त जेप्टो अपनी आपूर्ति श्रृंखला में 100 से अधिक भारतीय स्टार्टअप्स को जोड़ेगा जिससे उन्हें उत्पादों को प्रदर्शित करने, बाजार तक पहुंच प्राप्त करने और अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मंच मिलेगा।

डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव श्री संजीव ने इस अवसर पर कहा कि यूनिकॉर्न का समर्थन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक है जो उन्हें सफल उद्यमों की यात्रा के बारे में जानकर सीखने में सक्षम बनाता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके अनुकूल परिवेश में योगदान देना यूनिकॉर्न के लिए न केवल एक अवसर है बल्कि एक ज़िम्मेदारी भी है। स्टार्टअप्स के विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि बाजार तक पहुंच उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है।

समझौता ज्ञापन पर डीपीआईआईटी के निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और जेप्टो के सह-संस्थापक श्री कैवल्य वोहरा ने हस्ताक्षर किए।

जेप्टो के सह-संस्थापक श्री कैवल्य वोहरा ने कहा कि डीपीआईआईटी के साथ साझेदारी जेप्टो नोवा कार्यक्रम के माध्यम से विनिर्माण के बेहतर भविष्य को साकार करने में स्टार्टअप्स की सहायता करेगी।

यह समझौता ज्ञापन डीपीआईआईटी की साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रयासों का भाग है जो तीव्र गति से नवाचार, समावेशी आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को सक्षम बनाएगा।

पश्चिम रेलवे - राजकोट मंडल

ई-निविदा सूचना 29 वर्ष 2025-26 **दिनांक 11/08/2025**

ठेकेदार के स्वयं के PQRS पोर्टल के साथ CTR(P), TSR(P), TRR(P) और अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन

ई-निविदा संख्या: DRM-RJT-2025-26-E-70

कार्य का नाम: राजकोट मंडल - ठेकेदार के स्वयं के PQRS पोर्टल के साथ CTR(P), TSR(P), TRR(P) और अन्य संबंधित कार्यों का निष्पादन, वरिष्ठ मंडल अभियंता (पूर्व), राजकोट के अधिकार क्षेत्र में।

अनुमानित लागत: ₹.17,46,01,598.19	**बयाना राशि:** ₹.10,23,000.00
निविदा खोलने की दिनांक एवं समय: 04/09/2025, 15:00 Hrs.	
ऑफिस का पताः मण्डल रेल प्रबन्धक (इंजी.), पश्चिम रेलवे, कोठी कम्पाउण्ड, राजकोट, गुजरात - 360001	
वेबसाइट: www.ireps.gov.in	RJT 095

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

हर घर तिरंगा बाइक रैली भारत की अमृत काल की यात्रा को प्रदर्शित करती है: श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

(जीएनएस)।

स्वतंत्रता दिवस समारोह के आरंभ होने के उपलक्ष्य पर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम से एक भव्य "हर घर तिरंगा बाइक रैली" को हरी झंडी दिखाई गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और कई सांसदों ने इस देशप्रेम से भरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

जनसमूह को संबोधित करते हुए, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तिरंगे को एकता की शक्ति बताया जो नागरिकों को राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का परिकल्पित यह अभियान और उत्सव, पूरे देश में, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, उत्साह की लहर फैला रहा है।'

केंद्रीय मंत्री ने एकता और बलिदान के प्रतीक के रूप में तिरंगे के चिरस्थायी प्रतीकवाद पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से आए उत्साह का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि राष्ट्र अद्वितीय उत्साह और गौरव के वातावरण में डूबा हुआ है - जो सशस्त्र बलों के पराक्रम और भारत के प्रति गहरे सामूहिक स्नेह, दोनों का उत्सव मना रहा है।

उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना वाला आधुनिक 'अभियान और उत्सव' हर घर तिरंगा पहल के जरिए एक जन आंदोलन में विकसित हो गया है, जिससे एक भावना जो गहराई से प्रतिध्वनित हो रही है क्योंकि भारत आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत बनने के मार्ग पर अपने अमृत काल में आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एकता और गौरव की भावना को दोहराते हुए कहाः "भारत मां की जय के नारों के साथ, तिरंगा लिए हजारों बाइक सवार आज निकल पड़े। हमारे सांसदों से लेकर सैनिकों तक, देशभक्ति की भावना हवा में है। मैं इस राष्ट्रीय पर्व को घर-घर पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करती हूं।'

भारतीय झंडों के सागर और "भारत मां की जय" के उद्घोष से सजी इस रैली ने राष्ट्रीय राजधानी में देशभक्ति और एकता की भावना को दशार्ते हुए एक अद्भुत और भावनात्मक रूप से गूंजती यात्रा का चित्रण किया।

चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत, नागरिकों को 13 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों और कार्यस्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जेपी गोयल के निजी कागजात और दस्तावेजों के संग्रह का संकलन

(जीएनएस)।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के पुराने अभिलेखों का संरक्षक है और लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकों और शोधकताओं के उपयोग हेतु उन अभिलेखों को अपने पास रखने का दायित्व उस पर है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार एक प्रमुख अभिलेखीय संस्थान के रूप में अभिलेखीय चेतना को दिशा देने और उसे आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास सार्वजनिक अभिलेखों के विशाल संग्रह के अतिरिक्त सभी क्षेत्रों के उन प्रतिष्ठित भारतीयों के निजी कागजात और दस्तावेजों का ऐसा समृद्ध संग्रह है जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें निरंतर वृद्धि हो रही है।

श्री जे.पी. गोयल भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रख्यात वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद (राज्यसभा, 1982-88) रहे हैं। उन्होंने भारत के इतिहास में कई ऐतिहासिक कानूनी मुकदमों में

महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध ऐतिहासिक चुनाव याचिका में श्री राज नारायण के मुख्य अधिवक्ता के रूप में उनकी अहम भूमिका रही जिसके कारण 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई। वे श्री अशोक मेहता, श्री चंद्रशेखर और श्री बीजू पटनायक जैसे नेताओं से भी मिले थे।

आपातकाल के दौरान सक्रिय रहते हुए उन्होंने जेल में बंद विपक्षी नेताओं और भूमिगत नेताओं से मुलाकात की और उनके परिवारों के लिए प्रमुख संपर्क सूत्र बन गए। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में श्री जयप्रकाश नारायण के होने की पुष्टि करने वाले वे पहले व्यक्ति थे और उनका साक्षात्कार भी सुनिश्चित किया। आपातकाल (1975) के दौरान श्री जयप्रकाश नारायण के कारावास के दौरान वे कुछ समय के लिए उनके वकील भी रहे। विधिक मामलों में श्री गोयल की कुशलता ने 1973 के केशवानंद भारती मामले के उस निर्णय को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसने संविधान के मूल ढांचे की रक्षा की। इन वृत्तांतों का विस्तृत विवरण "सेविंग इंडिया फ्रॉम इंदिराः अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसीः मेमोआयर्स ऑफ जेपी गोयल" में दिया गया है।

श्री जेपी गोयल का जन्म 21 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के नाला गांव में हुआ था। (2011 से, नाला गांव नए जिले शामली का हिस्सा है।) अपने गांव के स्कूल और पास के कस्बों कांधला और बड़ौत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद और लखनऊ विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा जारी रखी जहां से उन्होंने क्रमशः एमए (अर्थशास्त्र) और एलएलबी की उपाधि प्राप्त की।

आधार की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए आईएसआई के साथ 5-वर्षीय अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर

यूआईडीएआई ने डेटा-आधारित नवाचारों के माध्यम से आधार की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के साथ 5-वर्षीय अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए

बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल्स, मैचिंग एल्गोरिदम और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए सहयोग

(जीएनएस)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने मंगलवार को भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के साथ संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डेटा-संचालित नवाचारों के माध्यम से आधार संचालन की मजबूती, सुरक्षा और विश्वसनीयता को और बढ़ाना है।

यह समझौता पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा और इसमें धोखाधड़ी और विसंगति का पता लगाने, बायोमेट्रिक सक्रियता पहचान उपकरणों का विकास, उच्च जोखिम वाले नामांकन/अद्यतन श्रेणियों की पहचान, बायोमेट्रिक मिलान एल्गोरिदम में सुधार और आपसी सहमति से तय किए गए अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।

इस समझौते पर यूआईडीएआई की उप महानिदेशक (प्रौद्योगिकी केन्द्र) सुश्री तनुश्री देब बर्मा और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बेंगलुरु केन्द्र के प्रमुख प्रोफेसर बी. एस. दया सागर ने हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर यूआईडीएआई के सीईओ श्री भुवनेश कुमार और भारत सरकार के कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) की अपर सचिव सुश्री पूजा सिंह मंडोल भी उपस्थित थीं।

यूआईडीएआई के सीईओ कुमार ने कहा, "भारतीय सांख्यिकी संस्थान के साथ हमारा सहयोग उन्नत, सुरक्षित और नागरिक-केन्द्रित नवाचार के निर्माण की दिशा में एक कदम है।"

आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मोटापा कम करने के लिए किये प्रयास

(जीएनएस)।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) के अनुसार, 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक मोटापे की बढ़ती व्यापकता के प्रमुख कारण हैं। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत, शारीरिक गतिविधियों में कमी और जीवनशैली में बदलाव ने इस बढ़ते संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी प्रभावित हो रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ताकि राज्यों के प्रयासों को पूरा किया जा सके। साथ ही बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, मानव संसाधन, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और मोटापे सहित जागरूकता पर ध्यान

केंद्रित किया जा सके।

भारत सरकार (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत स्वस्थ जीवन के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को बढ़ावा देती हैः आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कल्याण गतिविधियों और लक्षित संचार को बढ़ावा दिया जाता है।

आयुष मंत्रालय द्वारा योग संबंधी गतिविधियां संचालित की जाती हैं।

एनपी-एनसीडी के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता सृजन गतिविधियों (आईईसी) के लिए वित्तीय सहायता।

स्वस्थ जीवनशैली के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक एएएम में स्वास्थ्य मेले आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीमों द्वारा स्वास्थ्य जांच और परामर्श के दौरान स्कूली शिक्षकों और छात्रों को चीनी और तेल का सेवन कम करने के बारे में जागरूक किया जाता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सत्रों में इन संदेशों को शामिल करने के लिए किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों में सहकर्मी शिक्षकों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाता है।

विश्व हाथी दिवस 2025 पर भारत ने हाथी संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व की पुष्टि की

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में विश्व हाथी दिवस 2025 समारोह का उद्घाटन किया और हाथियों के संरक्षण के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।

विश्व हाथी दिवस पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत हाथियों के निवास स्थलों की रक्षा के लिए पारंपरिक ज्ञान के साथ एआई, रिमोट सेंसिंग और भू-स्थानिक मानचित्रण जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़कर उनके लिए एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।" उन्होंने स्थानीय समुदायों की

भलाई सुनिश्चित करते हुए मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच जुड़ाव, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा, "हाथी संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह हमारे सभ्यतागत मूल्यों और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व को प्रतिबिंबित करती है।" उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 33 हाथी अभयारण्यों, वैज्ञानिक रूप से चिन्हित150 गलियारों और दुनिया की लगभग 60% जंगली हाथियों की आबादी के साथ, भारत सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के एक वैश्विक उदाहरण के रूप में उभरा है - जहाँ कानूनी सुरक्षा, वैज्ञानिक योजना और सांस्कृतिक सम्मान मिलकर अपने राष्ट्रीय धरोहर पशु के भविष्य की रक्षा करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी खेलों में भारतीय घोड़ों की भागीदारी

(जीएनएस)।

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूओएएच) ने मेरठ के रिमाउंट पशु चिकित्सा केंद्र (आरवीसी) में स्थित अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (ईडीएफसी) को मान्यता प्रदान की है जो देश के घुड़सवारी खेलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे भारतीय घोड़ों को लंबे क्वारंटाइन के बिना अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पधाओं में शामिल होने का अवसर मिलता है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकें।

यह मान्यता भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल करती है जिनके पास वैश्विक स्तर के जैव सुरक्षा मानक हैं, इससे घुड़सवारी गतिविधियों में भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है और यह पशु देखभाल, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं खेलों में प्रगति को दशार्ती है।

अश्व रोग-मुक्त कम्पार्टमेंट (ईडीएफसी) एक मजबूत मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की संरचना के अंतर्गत कार्य करता है ताकि निरंतर रोग निगरानी सुनिश्चित की जा सके, उच्च जैव-सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जा सके, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ समन्वय किया जा सके।

ये एसओपी सभी महत्वपूर्ण कार्यों को कवर करते हैं, जिनमें क्वारंटाइन, अपशिष्ट प्रबंधन, कार्मिक आचरण, आपातकालीन प्रतिक्रिया एवं आवागमन नियंत्रण शामिल हैं।